

भारतीय वित्तीय प्रणाली में नीतिगत विकल्पों पर विचार*

एम राजेश्वर राव

I. परिचय: भारतीय वित्तीय प्रणाली- भारतीय स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष में भूत और भविष्य पर विचार

बैंकिंग बिरादरी के प्रतिष्ठित सदस्य, देवियों और सज्जनों

स्वर्गीय श्री आर के तलवार की महान विरासत का सम्मान करते हुए बारहवां स्मारक व्याख्यान देना सौभाग्य की बात है। मैं श्री आर के तलवार जैसे व्यक्तित्व को बैंकिंग उद्योग में उनके योगदान के लिए याद करने का अवसर प्रदान करने के लिए आभारी हूँ।

भारत ने हाल ही में अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाए हैं और इस अवधि के दौरान, हमारे देश ने नई वैश्विक व्यवस्था में एक आशाजनक और प्रमुख शक्ति के संक्रमण को देखा है। हालांकि, यात्रा पूरी होने से बहुत दूर है, और हमारी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए बहुत कुछ हासिल किया जाना बाकी है। इस तरह के अवसर हमें तय किए गए मार्ग, निरंतर और उभरती चुनौतियों और आगे के रास्ते पर विचार करने का अवसर देते हैं।

श्री आर. के. तलवार ने हमारे बैंकिंग इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर भारत के सबसे बड़े बैंक की बागडोर संभाली - राष्ट्रीयकरण की अवधि। उन्होंने वंचितों की सेवा के लिए वाणिज्यिक बैंकिंग को फिर से तैयार किया, जो राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों के साथ मूल रूप से संरेखित था। अभिनव बैंकिंग, बीमार इकाइयों के पुनर्वास, लघु उद्योगों के लिए सुविधाजनक और सुलभ वित्तपोषण और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रोत्साहन पर उनका जोर उनके दृष्टिकोण का प्रमाण है जो बाद में जिम्मेदार

* 21 अक्तूबर, 2022 को मुंबई में 12वां आर के तलवार स्मृति व्याख्यान भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम राजेश्वर राव द्वारा दिया गया। श्री वैभव चतुर्वेदी, श्री प्रदीप कुमार और श्री सौरभ प्रताप सिंह द्वारा प्रदान किए गए इनपुट को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार किया जाता है।

बैंकिंग की आधारशिला बन गया, जिसने हमारे देश में समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

आजादी के बाद से, हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में वृद्धि और विकास में भारी प्रगति की है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर 5 लाख करोड़ रुपये (1950-51) से बढ़कर लगभग 147 लाख करोड़ रुपये (2020-21) हो गया, जो लगभग 4.8 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ लगभग 27 गुना बढ़ रहा है। लेकिन इस विकास की कहानी की छाया में एक द्वंद्व है जो हर नीति निर्माता और चिंतित नागरिकों का ध्यान आकर्षित करता है। भले ही पिछले सात दशकों में जीडीपी 27 गुना बढ़ी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय लगभग 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर लगभग 14,000 रुपये (1950-51) से लगभग 1 लाख रुपये (2020-21) तक केवल सात गुना बढ़ी है, जिसमें लगभग 2.9 प्रतिशत की सीएजीआर है।¹ यह द्वंद्व हमारे देश के समावेशी विकास के महत्व और आवश्यकता पर प्रकाश डालता है - एक ऐसा लक्ष्य जिसकी हम सभी को आकांक्षा करनी चाहिए और अपनी संबंधित पेशेवर क्षमताओं में योगदान देना चाहिए।

वित्तीय प्रणाली के विकास में भी कई उतार-चढ़ाव आए हैं, जो किसी दिए गए सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में किए गए नीतिगत विकल्पों को दर्शाते हैं। जैसा कि आम तौर पर कहा जाता है, नीति निर्माण समाधान को किनारे करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। परिणाम अक्सर धुंधले मध्य में कहीं नहीं होते हैं, जो प्रासंगिक व्यापार-बंद को दर्शाते हैं। आज की अपनी टिप्पणी में, मैं इनमें से कुछ व्यापारों पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखता हूँ, विचार यह है कि उन्हें उनके अस्तित्व के लिए आंका जाए, या उनके प्रभावों के बारे में विचार न किया जाए, बल्कि उन विशिष्ट संरचनात्मक मार्गों को सामने लाया जाए जो हमारी वित्तीय प्रणाली ने पिछले सात दशकों के दौरान भारतीय विकास की कहानी को मजबूत करते हुए तय किए हैं।

इसलिए, मैं संक्षेप में भारतीय वित्तीय प्रणाली की कुछ ऐसी संरचनात्मक और विनियामक द्वंद्वों के बारे में बात करूंगा जो आगे के रास्ते पर अपने स्वयं के कुछ विचारों के साथ आगे बढ़ते हुए, कुछ प्रमुख प्रश्नों को संबोधित करने के अभिन्न अंग हैं, जिन पर मैं प्रकाश डालता हूँ।

¹ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, <https://mospi.gov.in/web/mospi/download-tables-data/-/reports/view/templateOne/28401?q=TBDCAT>

II. भारत में बैंक के नेतृत्व वाले बनाम बाजार के नेतृत्व वाली वित्तीय मध्यस्थता

क्या बैंक-प्रभुत्व वाली वित्तीय प्रणाली से गैर-बैंक मध्यस्थता चैनल में संक्रमण की कल्पना करना संभव है?

व्यापक अनुभवजन्य साक्ष्य और साहित्य हैं जो इस दावे की पुष्टि करते हैं कि किसी देश का आर्थिक विकास वित्तीय प्रणाली के विकास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जो बचत को इकट्ठा करने और उन्हें देश की उत्पादक क्षमताओं तक पहुंचाने की एक कुशल प्रणाली बनाता है।

जबकि बैंक ऋण ऐतिहासिक रूप से भारत में वित्तपोषण का एक प्रमुख स्रोत रहा है, इसे गैर-बैंक चैनलों द्वारा इस अवधि में पूरक किया गया है, जो पिछले एक दशक में काफी बढ़ गया है। भारत में अब 10 करोड़ से अधिक डीमैट खाते हैं और धन जुटाने के लिए प्राथमिक बाजार तक पहुंचने वाली संस्थाओं में तेजी आई है। इस गेम में अपेक्षाकृत नए प्रवेश करने वाले म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 40 लाख करोड़ रुपये की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) हासिल की हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में भी काफी वृद्धि हुई है, हालांकि संरचनात्मक रूप से यह बेहतर रेटेड कॉर्पोरेट्स तक ही सीमित है, जिसमें क्रेडिट वक्र में अपेक्षित पैठ एक स्थायी चुनौती बनी हुई है। कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने में लगातार वृद्धि हुई है और मार्च 2022 तक बकाया राशि 40 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार वित्तीय प्रणाली के भीतर एक जोखिम फैलाने वाले के रूप में कार्य करता है, निवेशकों के एक बड़े सेट के बीच जोखिम को पुनर्वितरित करता है।

जबकि बैंकों से बाजार-आधारित तंत्र में ऋण के प्रवाह में क्रमिक बदलाव स्पष्ट हो गया है, हमारे मामले में रास्ता लंबा रहा है क्योंकि हम अभी भी आर्थिक प्रणाली में बैंकों की केंद्रीयता देख सकते हैं। विडंबना यह है कि बैंक गैर-बैंक मध्यस्थता चैनल के कई बाजार खंडों का भी समर्थन कर रहे हैं - द्वितीयक बाजार तरलता के प्रदाताओं के रूप में, क्रेडिट बढ़ाने के लिए और बाजार निर्माताओं के रूप में। यह एक नियामक के रूप में रिजर्व बैंक के

काम को और भी महत्वपूर्ण बनाता है क्योंकि बैंकिंग प्रणाली के साथ सभी आर्थिक एजेंटों का परस्पर संबंध है।

सरकार, सेबी और रिजर्व बैंक ने कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार विकसित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सेबी ने मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डीवीपी निपटान, इलेक्ट्रॉनिक बोली मंच और ट्रेडों की रिपोर्टिंग के रूप में कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए एक बाजार माइक्रोस्ट्रक्चर स्थापित किया है। रिजर्व बैंक ने सेबी के प्रयासों को पूरा करने के लिए रेपो और सीडीएस जैसे पूरक बाजारों को विकसित करने का भी प्रयास किया है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि ऋण की बढ़ती आवश्यकता के साथ, स्रोतों को विविधीकरण की भी आवश्यकता होगी। यह बाजार प्रतिभागियों के बीच क्रेडिट जोखिम के प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण को सक्षम करेगा और उन कंपनियों को अधिक सौदेबाजी की शक्ति देगा जो अपने विकास और विस्तार को निधि देना चाहते हैं और इस प्रकार, वास्तविक क्षेत्र के लिए फायदेमंद होगा।

तथापि, मैं यहां इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें बैंकों की भूमिका अधिक और कम महत्वपूर्ण नहीं हो गई है - मध्यस्थता की समावेशिता - भौगोलिक और जनसांख्यिकीय दोनों। पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र ने इस संबंध में बहुत अधिक बोझ उठाया है, इस प्रक्रिया में बहुत सारी लागतों को अवशोषित किया है। अन्य चैनलों की तुलना में बैंकिंग प्रणाली के प्रदर्शन का कोई भी आकलन इस महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

III. स्वामित्व - पब्लिक सी बनाम निजी

क्या बहस में कोई बीच का रास्ता है?

उदारीकरण से पहले और बाद में भारतीय बैंकिंग प्रणाली की एक बहुत ही विशिष्ट विशेषता है। उदारीकरण से पहले, भारतीय अर्थव्यवस्था काफी हद तक एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जिसमें सरकार नियोजित विकास के लिए एक प्रमुख आर्थिक भूमिका निभा रही थी। यह आर्थिक संरचना समकालीन बैंकिंग संरचना के साथ अच्छी तरह से संरेखित थी, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास भारत में कुल बैंकिंग परिसंपत्तियों का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा था, खासकर बैंकों के राष्ट्रीयकरण (1969 और 1980) के दो प्रमुख एपिसोड के बाद।

भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की उत्पत्ति का श्रेय 1991 में श्री एम नरसिम्हन की अध्यक्षता वाली वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति की सिफारिशों को दिया जा सकता है (जिसे नरसिम्हन समिति-1 के नाम से जाना जाता है)। समिति की सिफारिशों के आधार पर, बैंकों के दोहरे विनियमन को हटाने का प्रस्ताव किया गया था, ब्याज दरों को काफी हद तक नियंत्रणमुक्त कर दिया गया था, बैंक पूंजी की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को कम किया गया था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के प्रवेश के साथ बैंकिंग क्षेत्र फिर से संगठित होना शुरू हो गया था। नए बैंकों को पेश करने का विचार बेहतर अनुकूलन दक्षता के लिए बैंकिंग प्रणाली की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना था।

अपने व्यवसाय की शुरुआत के बाद से, नए युग के निजी क्षेत्र के बैंक अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं में तेजी से योगदान दे रहे हैं। पिछले लगभग 25 वर्षों में, कुल ऋण में उनकी हिस्सेदारी 1996-97 में लगभग 3 प्रतिशत से बढ़कर 2021-212 में 36 प्रतिशत हो गई है।² जबकि निजी बैंकों की समस्याएं रही हैं, उनकी उपस्थिति ने वित्तीय प्रणाली को और अधिक लचीला बना दिया है और बैंक-ऋण और जीडीपी अनुपात में त्वरित वृद्धि के रूप में वित्तीय गहराई के प्रयासों को गति प्रदान की है, जो 1995 में लगभग 26.7 प्रतिशत से बढ़कर 20213 में लगभग 52 प्रतिशत हो गई है।³

जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों का संबंध है, उनकी भूमिका पर वर्षों से व्यापक रूप से बहस हुई है। बैंकिंग समेकन का विचार पहली बार नरसिम्हन समिति -1 में तीन-स्तरीय बैंकिंग संरचना की स्थापना के माध्यम से पेश किया गया था: i) अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति वाले तीन बड़े बैंक, ii) आठ से दस राष्ट्रीय बैंक, और iii) बड़ी संख्या में क्षेत्रीय और स्थानीय बैंक। यह तर्क दिया जाता है कि बड़े, समेकित बैंकों में बड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पैमाने और क्षमता की अर्थव्यवस्थाओं के कारण बेहतर जोखिम विविधीकरण हो सकता है। समेकन का उत्तरार्द्ध तर्क

अधिक प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि भारतीय कंपनियां, और उनकी सहवर्ती क्रेडिट आवश्यकताएं बढ़ती हैं।

भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समेकन की सुविधा प्रदान कर रही है। नतीजतन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 (मार्च 2017 तक) से घटकर 12 (जून 2022 तक) हो गई है। इसी अवधि के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या 21 पर स्थिर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण का उनकी पहुंच या समावेशी बैंकिंग प्रयासों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि विलय से पहले और बाद में बैंक शाखाओं की कुल संख्या काफी हद तक समान रही है (युक्तिकरण के कारण मामूली कटौती के साथ)। इसके अलावा, वित्तीय समावेशन के प्रयास पहले ही प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाले एक व्यापार संवाददाता के नेतृत्व वाले मॉडल तक पहुंच गए हैं।

व्यापक स्तर पर, समान अवसर प्रदान करने के लिए, प्रत्येक वर्ग की इकाइयों के लिए उपलब्ध ऑपरेटिंग स्पेस और लचीलेपन के संदर्भ में एक क्रमिक अभिसरण होना होगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकिंग परिचालनों को नियंत्रित करने वाले विनियामक और विवेकपूर्ण मानदंडों के संदर्भ में, पहले से ही अभिसरण की एक महत्वपूर्ण मात्रा है। इसलिए, विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से, बहस निरर्थक है। तथापि, कतिपय शासन मानकों के आधार पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधकीय और परिचालनात्मक लचीलेपन के लिए अभिसरण के समान स्तर का विस्तार करना होगा। आने वाले समय में, यह पीएसबी के साथ-साथ निजी बैंकों दोनों के लिए अपने व्यवसाय को बढ़ाने और पनपने के लिए आवश्यक स्थान उत्पन्न करेगा।

IV. व्यापार मॉडल - विविध बनाम विशेष

क्या विशिष्ट बैंकिंग, विशेषीकृत बैंकिंग का वादा अभी भी कायम है?

व्यापक डिजिटल क्रांति और भारतीय घरों में इंटरनेट की व्यापक पहुंच के साथ, 21वीं सदी की बैंकिंग प्रथाओं को भारत की नई आकांक्षाओं के साथ संरेखित करने की आवश्यकता महसूस की गई। इस उभरते परिदृश्य के आधार पर, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के तत्कालीन सदस्य डॉ नचिकेत मोर की

² भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, आरबीआई, सितंबर 2022।

³ अंतरराष्ट्रीय निपटान के लिए बैंक।

अध्यक्षता में एक समिति का गठन छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों को व्यापक वित्तीय सेवाओं के दायरे का अध्ययन करने के लिए किया गया था। समिति ने 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और क्षेत्रीय/व्यापारिक क्षेत्रवार और गतिविधियों (जमा, लेनदेन या ऋण) के आधार पर अलग-अलग विशिष्टता वाले बैंकों के गठन सहित कैतिज और ऊर्ध्वाधर दायरे के आधार पर भारत में 'विभेदीकृत बैंकिंग' के विचार पर चर्चा की। 'भुगतान बैंक' की अवधारणा पर पहली बार उस रिपोर्ट में चर्चा की गई थी जिसने विभेदीकृत बैंकिंग पर औपचारिक संवाद शुरू किया था।

इसके बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2014-15 के बजट भाषण में घोषणा की कि आरबीआई लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और अन्य विभेदीकृत बैंकों को लाइसेंस देने के लिए एक ढांचा तैयार करेगा। घोषणा के अनुसार, रिजर्व बैंक ने नवंबर 2014 में एसएफबी और भुगतान बैंक (पीबी) स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। लाइसेंसिंग दिशा-निर्देशों⁴ में यथा परिकल्पित एसएफबी की स्थापना का विनिर्दिष्ट उद्देश्य बचत माध्यमों के प्रावधान द्वारा वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना और उच्च प्रौद्योगिकी-कम लागत वाले परिचालनों के माध्यम से लघु व्यवसाय इकाइयों; लघु और सीमांत किसानों; सूक्ष्म और लघु उद्योगों; और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को ऋण की आपूर्ति में वृद्धि करना है। इसी तर्ज पर, प्रवासी श्रमिक कार्यबल, कम आय वाले परिवारों, छोटे व्यवसायों, अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं और अन्य उपयोगकर्ताओं⁵ को लघु बचत खाते और भुगतान/प्रेषण सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पीबी की स्थापना की गई थी।

अपनी स्थापना के बाद से, एसएफबी ने वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए अपने विशिष्ट ग्राहक क्षेत्रों से बचत जुटाने और ऋण प्रदान करने में प्रगतिशील भूमिका निभानी शुरू कर दी है। मार्च 2018 के बाद से एसएफबी की कुल जमा और ऋण में वृद्धि महत्वपूर्ण रही है। मार्च 2022 को समाप्त तिमाही में, जमा में सालाना आधार पर 37.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि

एससीबी की जमा और ऋण की वृद्धिदर⁶ क्रमशः 10.2 प्रतिशत और 10.8 प्रतिशत की तुलना में ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि 25.6 प्रतिशत थी। हालांकि, पैमाने के प्रभावों के कारण सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की संबंधित संख्या की एसएफबी से तुलना करना अनुचित होगा, यहां तक कि बैंक शाखाओं के माध्यम से आउटरीच के मामले में भी, एसएफबी वर्तमान में भारत में बैंक शाखा नेटवर्क का लगभग 4 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं, जो 2017⁷ में 1 प्रतिशत से भी कम था।

भुगतान बैंक वास्तव में पहली पीढ़ी के नए युग के विभेदीकृत बैंक हैं जिन्हें गतिविधि आधारित कार्यात्मक विभेदीकरण के अनुसार डिजाइन किया गया है। डिजिटल भुगतान अर्थव्यवस्था और आपके द्वार बैंकिंग पर इन बैंकों के प्रभाव का आकलन केवल उनकी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस से नहीं किया जा सकता है, बल्कि सुगम डिजिटल लेनदेन के आंकड़ों से भी किया जा सकता है। आप सभी को इस पर एक परिप्रेक्ष्य देने के लिए, भुगतान बैंकों ने जून 2020 के महीने में मूल्य के आधार पर 17,465 करोड़ रुपये की राशि के कुल 11.4 करोड़ मोबाइल बैंकिंग लेनदेन की सुविधा प्रदान की, जो केवल दो वर्षों (अगस्त 2022) में लगभग 46,338 करोड़ रुपये के कुल मूल्य के साथ 47.3 करोड़ लेनदेन तक बढ़ गया है, जो मात्रा के मामले में 4.1 गुना और मूल्य के मामले में 2.7 गुना बढ़ गया है। यह भी रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि अगस्त 2022 तक, भुगतान बैंकों के 2.5 करोड़ सक्रिय उपयोगकर्ता अपनी मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग कर रहे थे, जो भारत में सभी सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं⁸ का लगभग 2.7 प्रतिशत था।

पूर्व में किये गए उल्लेख के अनुसार एक विभेदीकृत बैंकिंग संरचना का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय सेवाओं और संस्थानों की पहुंच का विस्तार करना था, जिसमें वित्तीय समावेशन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसलिए, विभेदीकृत बैंकिंग संस्थानों का अंतर्निहित आधार विभेदीकृत पहुंच पर आधारित है। जैसा कि हम सभी अब अनुभव कर रहे हैं, लगभग सभी बैंकों ने वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के वितरण में सुधार और विस्तार करने के लिए

⁴ लघु वित्त बैंकों को लाइसेंस देने के लिए दिशानिर्देश, आरबीआई https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=32614

⁵ भुगतान बैंकों को लाइसेंस देने के लिए दिशानिर्देश, आरबीआई https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=32615

⁶ वाणिज्यिक बैंक एक नजर में, डीबीआईई, आरबीआई

⁷ तिमाही के अंत तक वाणिज्यिक बैंकों के कार्यशील कार्यालयों की बैंक-वार संख्या, डीबीआईई, आरबीआई

⁸ ईसीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस/मोबाइल लेनदेन में बैंक वार मात्रा, डेटा रिलीज, आरबीआई

प्रौद्योगिकी को अपनाया है या अपना रहे हैं। रिजर्व बैंक बैंकिंग सेवाओं के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता में सुधार के लिए प्रगतिशील उपाय कर रहा है और इस प्रक्रिया को हाल ही में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) के शुभारंभ से महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है।

इन डीबीयू को आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लक्षित डिजिटल बैंकिंग अभियान के लिए 75 जिलों में स्थापित किया जाएगा। ये डीबीयू ग्राहकों को कागज रहित, कुशल, सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में डिजिटल मोड / चैनलों के माध्यम से डिजिटल यात्रा शुरू करने में सुविधा प्रदान करेंगे, वित्तीय समावेशन को बढ़ाएंगे और जनता को निर्बाध और कुशल तरीके से वित्तीय सेवा उत्पादों की पूरी शृंखला उपलब्ध कराएंगे तथा उनके बैंकिंग अनुभव को बढ़ाएंगे। ये डीबीयू डिजिटल बैंकिंग पर विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता पैदा करने में भी मदद करेंगे, डिजिटल वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के प्रति ग्राहकों के बीच हिचकिचाहट को कम करेंगे और इस तरह डिजिटलीकरण को तेजी से अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

डीबीयू की स्थापना देश में बैंकिंग सेवाओं के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को संरक्षित करने और एक निर्बाध बैंकिंग अनुभव की सुविधा प्रदान करने के लिए एक उल्लेखनीय कदम है। भारतीय अर्थव्यवस्था⁹ के वित्तीयकरण को बढ़ाने और वित्तीय समावेशन की गति में तेजी लाने की संभावना को देखते हुए, विभेदीकृत वित्तीय संस्थानों के संचालन और विकास के लिए पर्याप्त स्थान मौजूद है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अपेक्षित वित्तीय सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए व्यवसाय मॉडल पर्याप्त रूप से मजबूत होना चाहिए; और अपने वांछित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते समय उत्तम अभिशासन और तकनीकी मानकों का पालन किया जाना चाहिए।

V. नवाचार बनाम ग्राहक संरक्षण

वित्तीय सेवाओं में प्रौद्योगिकी-सक्षम नवाचार बैंकिंग के पारंपरिक तरीके के लिए सबसे बड़े विघटनकर्ताओं में से एक रहा

⁹ एक अर्थव्यवस्था के वित्तीयकरण को वित्तीय बाजार की बढ़ती गहराई और आकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस संदर्भ में, मैं इसे अपने सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में अर्थव्यवस्था में वित्तीय आस्तियों की मात्रा का उल्लेख करता हूँ।

है। उधार देने के वैकल्पिक मॉडल तेजी से बाजार की गतिशीलता को बदल रहे हैं और पारंपरिक मध्यस्थों की भूमिका को प्रभावित कर रहे हैं। एक ओर जहाँ, बैंकों के पास कम लागत वाली जमा तक पहुंच है, तकनीकी फर्मों का लाभ यह है कि प्रौद्योगिकी की सहायता से वे ऋण-योग्यता या किसे उधार देना है इसका मूल्यांकन करने के लिए डेटा / वैकल्पिक इनपुट की एक शृंखला का उपयोग कर सकते हैं। नियामकीय दृष्टिकोण से, जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तर्क हैं कि उधार देने के पारंपरिक माध्यम जारी रहें, एक विचार है कि विनियामक, फिनटेक वाले नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए अनिच्छुक हैं और इस दृष्टिकोण को बैंकों के पक्ष में गलत तरीके से संतुलन बनाए रखने के रूप में देखा जाता है। मेरे विचार से यह सही अनुमान नहीं होगा; वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने से रोकने के लिए तकनीकी परिवर्तनों को आवश्यकतानुसार मात्रा में आत्मसात करने की जरूरत है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले नवाचार के विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, लेकिन वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को संरक्षित करना नियामकों के लिए एक सर्वोपरि उद्देश्य है और नवाचार को बढ़ावा देते हुए स्थिरता सुनिश्चित करने का सही संतुलन प्राप्त करना लक्ष्य बना हुआ है। इसलिए, नियामकों को उम्मीद है कि पारंपरिक बैंकों और नए फिनटेक प्रतिभागियों के बीच साझेदारी की प्रकृति एक सहजीवी में विकसित होगी, और जरूरी नहीं कि एक प्रतिकूल हो।

यह सभी हितधारकों के लिए जीत की तरह है, लेकिन नियामकीय परिधि के बाहर होने वाली वित्तीय गतिविधियों से संबंधित जोखिमों के कारण उत्पन्न परोक्षी मध्यस्थता उत्पन्न हो सकने वाली एक चुनौती है। डिजिटल ऋण पर हालिया दिशानिर्देश प्रतिस्पर्धी विचारों को संतुलित करते हुए एक सक्षम ढांचा बनाने का एक प्रयास है।

वित्तीय सेवाओं के वितरण में अधिकांश नवाचारों में आचरण का एक अंतर्निहित पहलू है - शोषक बनाम जिम्मेदार आचरण के बीच चयन। 'जिम्मेदार' क्या है, इसका एक सामान्य भाजक स्थापित करना महत्वपूर्ण है। इस समस्या का समाधान करते समय इस आयाम में बहुत अधिक व्यक्तिपरकता है।

नैतिक और जिम्मेदार बैंकिंग, उन लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, समाज के कमजोर

वर्गों के प्रति हमारे दृष्टिकोण में समावेशी होना, विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेना - ये सभी विकल्प हैं जो वित्तीय क्षेत्र में लगे हम में से प्रत्येक के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। बैंकिंग बिरादरी समाज का ट्रस्ट वाहक होने के नाते लोगों और देश के प्रति संवेदनशील, समावेशी, जिम्मेदार और विवेकपूर्ण होने का दायित्व निभाता है।

हमारे वित्तीय संस्थानों ने इन विकल्पों से मार्गदर्शन प्राप्त किया है और आगे भी मार्गदर्शन प्राप्त करना जारी रखेंगे। परिणामों से बेखबर अनुचित तरीकों को अपनाने से अल्पावधि में लाभ मिल सकते हैं, लेकिन लंबे समय में संगठन को बड़ा नुकसान होगा। आखिरकार, वित्तीय संस्थान कुछ वर्षों के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए इस व्यवसाय में हैं। इसलिए, विशुद्ध रूप से व्यावसायिक दृष्टिकोण से, सभी हितधारकों के हित में कार्य करना समझदारी भरा है। सभी पहलुओं- किफ़ायती, पहुंच, और विशेष रूप से उपयुक्तता का पालन किया जाना चाहिए, जब कभी भी हम कोई वित्तीय उत्पाद डिजाइन करते हैं या इसे वितरित करते हैं। उपरोक्त में से किसी का भी उल्लंघन करना बिल्कुल भी विकल्प नहीं हो सकता है।

VI. समापन टिप्पणी

मैंने संक्षेप में भारतीय वित्तीय प्रणाली की महत्वपूर्ण द्वैतताओं को उजागर करने का प्रयास किया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, मैं इनमें से किसी भी श्रेणी का न्याय करने का इरादा नहीं रखता हूँ। इन दोहरेपनों को सामने लाने का एकमात्र उद्देश्य हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था के जवाब में भारतीय वित्तीय प्रणाली के बड़े पैमाने पर जैविक विकास पर जोर देना है और इस बात पर प्रकाश डालना है कि आरबीआई के नियामकीय ढांचे ने देश की बदलती जरूरतों को पूरा करने में मदद की है। वित्तीय प्रणाली में विकास के हर मोड़ पर, हर गांठ पर, एक नियामक के लिए असंख्य नीतिगत विकल्प हैं। आज हम जो निर्णय लेते हैं उनमें हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य को आकार देने की क्षमता है। लेकिन कभी-कभी, हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि इसके बारे में क्या हो सकता है और इस तरह के किसी प्रभाव का उत्तर देना मुश्किल है। लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली की गहराई, आकार और सुदृढ़ता अतीत में विभिन्न चौराहों पर लिए गए इस तरह के निर्णयों के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार है। कोई यह तर्क दे सकता है कि ये नीतिगत विकल्प आवश्यक रूप से पहले से सक्रिय नहीं थे, लेकिन कभी-कभी प्रतिक्रियाशील भी थे। सच ! केंद्रीय बैंकों को स्वतंत्र

रूप से नवाचार करने की स्वतंत्रता नहीं है, हमें अपने जनादेश और वित्तीय स्थिरता को पहले रखना होगा। ऐसे समय रहे हैं जब हमारी विवेकपूर्ण नीतियों के लिए हमारी सराहना की जाती है और ऐसे समय होते हैं जब रुढ़िवादी होने के लिए हमारी आलोचना की जाती है। लेकिन मैं आपको आश्चस्त करता हूँ कि हम जो कुछ भी करते हैं, हम व्यापक रूप से जनहित में कार्य करने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रत्येक नीतिगत रुख हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था की आवश्यकता और वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करने के लिए अनुकूलित है, और यह हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है।

एक पारंपरिक व्यवस्था में, बैंकिंग विनियमन में कुछ पूर्व-निर्दिष्ट टूलकिट होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और विश्व स्तर पर अपनाए जाते हैं। प्रत्येक वित्तीय संकट नियामकों को कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, और टूलकिट को प्राप्त सीख के अनुसार संशोधित किया जाता है। लेकिन, गतिशील रूप से विकास की ओर अग्रसर वित्तीय प्रणाली के साथ, नियामकों के पास मौजूदा साधनों पर अत्यधिक भरोसा करने की स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि उभरती वित्तीय व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली कई संभावित चुनौतियों का अनुमान नहीं होता है। दुनिया भर में, नियामक वक्र से आगे रहने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे इस वातावरण में प्रतिक्रियाशील होने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। जिन परिवर्तनों को हम महत्वहीन महसूस करते हैं, वे अब बहुत कम समय में कई गुना बढ़ सकते हैं जो वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इसलिए, हमें आसपास होने वाले सभी वित्तीय परिवर्तनों के बारे में जागरूक होना होगा और ऐसे परिवर्तनों का उचित जवाब देना होगा। जैसा कि नियामकीय परिधि धीरे-धीरे अज्ञात डोमेन तक फैल रही है - जलवायु वित्त, डिजिटल उधार का विनियमन, आदि; इनमें से कुछ विषय और भी प्रासंगिक हो जाएंगे।

इस संक्रमण काल में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमने कुछ व्यापक सिद्धांतों को ठीक करने की कोशिश की है जो सकारात्मक बाह्यताओं के साथ नवाचारों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाते हुए, किसी भी वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए नीतिगत रुख को पर्याप्त अनुकूल बनाते हैं। व्यापक स्तर पर, तीन मार्गदर्शक सिद्धांत जो आगे चलकर वित्तीय विनियमन तैयार करने में सहायक होंगे - सिद्धांत-आधारित, आनुपातिक और गतिविधि-आधारित विनियमन। एक अनिश्चित कारोबारी माहौल में, वित्तीय लेनदेन के सभी संभावित परिदृश्यों की भविष्यवाणी करना और फिर उसे निर्धारित करना

बहुत मुश्किल है। इसलिए, इस तरह के जटिल अधिरचना की आवश्यकता है कि नियामक को नियम-आधारित आदेशात्मक अभिशासन से सिद्धांत-आधारित अभिशासन में स्थानांतरित करना चाहिए और विनियमन के सिद्धांतों के मूल में हमेशा वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ताओं के हित होने चाहिए।

वर्तमान और भविष्य के विनियमन के लिए दूसरा सिद्धांत आकार, जटिलता और प्रणालीगत जोखिम में योगदान के आधार पर एक विभेदीकृत नियामक प्रणाली होनी चाहिए। इसके अलावा, जैसे-जैसे परस्पर संबंध, गतिविधियों का दायरा और वित्तीय मध्यस्थता का सामंजस्य बढ़ता है, इकाई-आधारित विनियामकीय संरचना समान गतिविधि करने वाली विभिन्न संस्थाओं के बीच अंतरपणन पैदा कर सकती है। इसलिए, आगे बढ़ते हुए, गतिविधि को भविष्य के नियमों के लिए एक सर्वनिष्ठ विनियामकीय विचार बनाना चाहिए।

मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की प्रसिद्ध कविता की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, जो न केवल मेरे द्वारा कही गई बातों से मेल खाती है, बल्कि इस व्याख्यान के विषय-नीति विकल्पों पर प्रतिबिंब को भी छूती है:

“घने जंगलों से दो रास्ते गुजरते हैं,

क्षमा करें कि मैं दोनों की यात्रा न कर सका...

मैंने उसे चुना जिसपर कम लोगों ने यात्रा की,

और इसी से बड़ा अंतर स्थापित हुआ”

इस व्याख्यान के आयोजन और मुझे अपने विचार साझा करने का अवसर देने के लिए पुनः एक बार आईआईबीएफ को धन्यवाद। मुझे इतना धैर्यपूर्वक सुनने के लिए सभी प्रतिष्ठित अतिथियों को धन्यवाद।

आप सभी को धन्यवाद!